

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2279

शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

पटियाला के राजपुरा में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर का कार्यान्वयन

2279. डा. विक्रमजीत सिंह साहनी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या अमृतसर - कोलकाता औद्योगिक गलियारे (एकेआईसी) के अंतर्गत पटियाला के राजपुरा में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) का कार्यान्वयन अनुमोदित समय-सीमा के अनुसार किया जा रहा है;
- (ख) भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरीयों, ट्रंक अवसंरचना संबंधी कार्य और प्रोग्राम मैनेजर फॉर न्यू सिटीज (पीएमएनसी) की नियुक्ति की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) क्या पंजाब सरकार के पास लंबित मंजूरीयों अथवा उससे अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई नहीं होने के कारण कार्यान्वयन में कोई विलंब हुआ है; और
- (घ) औद्योगिक आवंटन आरंभ किए जाने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है और परियोजना में होने वाले अनुमानित निवेश एवं रोजगार सृजन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): जी, हां। भारत सरकार ने अगस्त, 2024 में अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर (एकेआईसी) के अंतर्गत पंजाब के पटियाला जिले के राजपुरा में 1,098.85 एकड़ क्षेत्र में 1,367.72 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत से एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (आईएमसी) के विकास को अनुमोदन प्रदान किया है। इस परियोजना के लिए नए शहरों हेतु कार्यक्रम प्रबंधक (पीएमएनसी) तथा इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति एवं निर्माण संविदाकार (ईपीसीसी) नियुक्त किए जा चुके हैं।

परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

- **भूमि अधिग्रहण:** 1,098.85 एकड़ के कुल परियोजना क्षेत्र में से 1,089.74 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

- **पर्यावरणीय मंजूरी:** जून, 2025 में पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।
- **मुख्य अवसंरचना कार्य:** मुख्य अवसंरचना के कार्यान्वयन हेतु मार्च, 2026 में इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति एवं निर्माण (ईपीसी) संविदाकार की नियुक्ति की गई।
- **नए शहरों हेतु कार्यक्रम प्रबंधक (पीएमएनसी):** सितंबर, 2025 में नए शहरों हेतु कार्यक्रम प्रबंधक (पीएमएनसी) को नियुक्त किया गया।

परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा के अनुसार परियोजना में किसी प्रकार का विलंब नहीं हुआ है। विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा की गई कार्रवाई निम्नानुसार है:-

- i. सितंबर, 2025 में निविदा आमंत्रित की गई।
- ii. जनवरी, 2026 में तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन पूरा किया गया।
- iii. फरवरी, 2026 में ईपीसी संविदाकार को एलओए जारी किया गया।
- iv. मार्च, 2026 में ईपीसी संविदाकार के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।

उद्योगों को भूमि का आवंटन, संबंधित विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) द्वारा अनुमोदित भूमि आवंटन नीति के अनुसार किया जाता है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, इस परियोजना से लगभग 7,500 करोड़ रुपए के निवेश तथा लगभग 64,200 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।
